

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]
No. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1966 (चैत्र 5, 1888)
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1966 (CHAITRA 5, 1888)

इस भाग में पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 10 मार्च 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 10th March 1966 :—

सं० Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
41.	Finance Ministry's Budget speech for the year 1966-67.	1966-67.	
42.	Corrigendum dated 3rd March/66.	Min. of Commerce	Import of Boilers and parts thereof.
43.	No. P. N. (U.S.A. Licensing) 1 of 1966, dt. 5th March/66.	Do.	Scheme for the licensing of restricted varieties of Indian Cotton Textiles for export to the U.S.A. during the next 6 monthly licensing period 1st April, 1966 to 30th Sept. 1966.
44.	सं० 11 (33)/65-ई० ए० सी० दिनांक 4 मार्च 1966.	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्य गति का पुनरीक्षण करने के लिए समिति।
45.	No. F. 4 (28)/W & M/65, dt. 9th March/1966.	Min. of Finance.	Stoppage of subscriptions to the Govt. of India 4½ per cent National Defence Loan, 1968 and 4½ per cent National Defence Loan, 1972 from 1st April/66.
46.	No. 37-ITC(PN)/66, dt. 9th March/66.	Min. of Commerce	Import of (i) fruits all sorts excluding coconuts and cashewnuts, fresh, dried, salted or preserved, n.o.s. and excluding dates S. No. 21(a) (IV) (ii) Asafoetida S. No. 31 (b)(V) (iii) Cumin seeds and (iv) Medicinal herbs from Afghanistan during 1966-67 Trade Arrangement period.
	No. 38-ITC(PN)/66, dt. 9th March/66.	Do.	Import of Hides & Skins raw or salted S. No. 144/IV from Afghanistan during 1966-67 Indo-Afghan Trade Arrangement period (1st Feb. 1966 to 31st Jan. 1967).
47.	No. 1-ETC(PN)/66, dt. 10th March/66.	Do.	The export of Ethyle Alcohol will be canalised through stage Trading Corporation of India.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची (CONTENTS)

पृष्ठ (Pages)	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. 277	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. 13
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं .. 275	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं .. 183
	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. --
	भाग II—खंड 2—प्रिजेयफ और प्रिजेयफों संबंधी प्रवर अधिनियमों की रिपोर्ट .. --

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	455	भाग III—खंड 2—एकत्र कार्यलय, कसकला द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	115
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	803	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	35
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	73	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	209
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	201	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	65
		पुरक सं० 13—	
		19 मार्च 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	427
		26 फरवरी 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े	439
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	277	PART II—SECTION 3.—Sub-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	803
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	275	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	73
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	13	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	201
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	183	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	115
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	35
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	209
PART II—SECTION 3.—Sub-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	455	PART IV—Advertisement and Notices by Private Individuals and Private Bodies	65
		SUPPLEMENT No. 13—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 19th March 1966	427
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 26th February 1966	439

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1966

सं० 31-प्रेज/66—शनिवार दिनांक 3 जुलाई, 1965 के भारतीय राजपत्र के भाग I अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 41-प्रेज/65, दिनांक 23 जून, 1965 में “लहाख-1962” एवं “नेफा-1962” के कलैस्पो की शुरुआत के सम्बन्ध में पैरा 2 II (क) V में निम्न संशोधन किया जाय :—

दिनांक “26 अक्तूबर” के स्थान पर “25 अक्तूबर” पढ़ा जाय ।

ध० जे० मोर, राष्ट्रपति के उप-सचिव

योजना आयोग

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 1966

संकल्प

सं० III-1(2)/65-सि० व० बि०—योजना आयोग के दिनांक 27-12-1965 के अनुपूरक द्वारा आशाधित भारत सरकार, योजना आयोग के संकल्प सं० III-1(2)/65-सि० व० बि०, दिनांक 2-7-1965 में निम्न संशोधन किया जाता है । सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली परियोजनाओं से सम्बन्धित सलाहकार समिति के गठन के विषय में दिनांक 2-7-1965 के संकल्प के पैरा 4 में, मद (1) के सामने “उप-मंत्री सिंचाई व बिजली—अध्यक्ष” के स्थान पर “सिंचाई और बिजली के राज्य मंत्री—अध्यक्ष” पढ़िए । मद (11) के सामने

“सभापति, इन्स्टीच्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया)” के स्थान पर “सभापति वा भूतपूर्व सभापति, इन्स्टीच्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया)” पढ़िए ।

मद (12) के सामने

ओड़िए—“अणु शक्ति आयोग का एक प्रतिनिधि”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, राज्यों में मुख्य मंत्रियों, भारत सरकार के सब मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों को भेज दी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाय ।

जी० आर० कामत, सचिव

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 1966

संकल्प

सं० 101(26/65-पी० पी० डी०—भविष्य में पेट्रोलियम उत्पादों के शोधनशाला और आयातित मूल्यों तथा उनसे सम्बन्धित अन्य विषयों के निर्धारण करने की पद्धति पर सलाह देने के लिए; पश्चिमी बंगाल सरकार के भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री जे० एन० तालुकदार की अध्यक्षता में 12 मई, 1964 को स्थापित किये कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने ध्यान पूर्वक विचार किया है ।

2. इस विषय में सरकार ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कुछ दिनों से सामने आ रहे थे, ध्यान में रखा है । वे निम्न प्रकार हैं :—

- (क) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि एवं स्थानीय तथा आयातित दोनों प्रकार के कच्चे तेलों पर आधारित देशीय शोधन-क्षमता की वृद्धि; और
- (ख) इसके परिणाम स्वरूप सज्जित उत्पादों के आयात में बराबर और पर्याप्त कमी और ऐसे आयातों की शर्तों में परिवर्तन ।

अन्य विषयों के अतिरिक्त इन विकासों से ये आवश्यक होता है कि देशीय कच्चे तेल के उत्पादनकर्ताओं को देश में अन्वेषण की लागतों एवं उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मूल्य का आश्वासन मिले । अभी तक जो पद्धति अपनाई जाती रही है वह यह है कि उपभोक्ताओं को दिये गये देशीय कच्चे तेल का दाम आयातित कच्चे तेल के समय-समय पर बढ़ागत एवं घटते-बढ़ते मूल्यों की बराबरी पर निर्धारण किया जाता रहा है । कच्चे तेल के आयातों पर सरकार, काफी सफलता के साथ विश्व बाजार की स्थितियों के अनुसार मूल्यों को प्राप्त करने का यत्न करती रही है । बिल्कुल व्यापारिक विचारों पर न्याय संगत होने के अतिरिक्त, देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण के लिए, उचित एवं युक्ति संगत स्तरों पर आयात मूल्यों की स्थापना महत्वपूर्ण है । अतः सरकार को जैसी जरूरत होगी उपलब्ध सारे साधनों सहित इस उद्देश्य की प्राप्ति में कार्य को जारी रखेगी । किन्तु इस स्थिति में देशीय कच्चे तेल के मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि देश में व्यापी परिस्थितियों में तेल अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यों के लिए आर्थिक आधार उपलब्ध नहीं है । दूसरे शब्दों में, देशीय कच्चे तेल उत्पादकों की किसी प्रकार के सुरक्षा के लिए एक ऐसी पद्धति को शुरू करना आवश्यक है जिस से उन्हें एक ऐसे मूल्य का आश्वासन मिले जोकि समय-समय पर उनके कार्यों की लागत के मुताबिक हो । कच्चे तेल के ऐसे मूल्यों की संगति, तथा युक्तिसंगत स्तरों पर शोधन के कार्यों की आर्थिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए शोधन-शालाओं पर उत्पादन मूल्यों का समुचित पुनः निर्धारण करना

चाहिए। इसका आयात होने वाले उत्पादों की, जो सबसे अच्छी उपलब्ध शर्तों पर जिस मात्रा तक अपेक्षित हों, की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. उपर्युक्त विचारों के आधार पर ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किया है :—

(i) आगामी आदेशों तक, देशीय कच्चे तेल के उत्पादकों को उन मामलों के अतिरिक्त जिनमें सरकार और उत्पादक के बीच में हुए करार के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण के लिए एक विभिन्न आधार हो, एक मूल्य प्राप्त होगा जो मध्य पूर्व से अनुरूप आयातित कच्चे तेल पर लगाये गये जहाज पर दामों (F.O.B. Prices) के आधार पर आंकित उतारने की लागत (landed cost) (आयात शुल्क, यदि कोई हो, को नहीं शामिल करते हुए) के मुकाबले में कम नहीं होगा। देशीय कच्चे तेल के हस्तेमाल करने वालों को, इस मूल्य आधार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित या प्रार्थना की जायेगी, जैसा भी मामला हो। यदि और जब कभी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, सरकार इस समय निर्धारित किये गये मूल्य नीति पर पुनः विचार करेगी।

(ii) देश में सारी शोधनशालाओं के बहुल शोधित उत्पादों के शोधनशाला पर के मूल्यों और उतारे गये मूल्यों को जब वे लागू होंगे; आयात साम्य के आधार पर निर्धारित किया जायेगा जो कि जैसा 18-5-1965 को अवादान (प्लाट्ट के सब से कम) पर लगाये गये जहाज पर पूर्ण रूप (अर्थात् बिना बढ़ागत) लागत से शुरू होगा।

(iii) समय-समय पर व्यापी सम्बन्धित परिस्थितियों द्वारा निर्धारित स्तर पर आयातित कच्चे तेल पर एक संरक्षण आयात कर लगाया जायेगा।

4. उपर्युक्त आधार पर सरकार ने प्रचुर शोधित उत्पादों, विट्र्यूमेन लुब्रीकेण्ट्स, ग्रीज एवं विशेष पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के बारे में कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है तथा यह फैसला किया गया है कि निम्नलिखित संशोधनों का ध्यान में रखते हुए उनको 1 फरवरी 1966 से अपनाया एवं लागू किया जाए :—

(क) प्रचुर शोधित पेट्रोलियम उत्पादों (विट्र्यूमेन को शामिल करते हुए), के बार में, 18 मई 1965 को अपनाये गये आधारों पर अवादान (प्रचुर शोधित उत्पादों के बारे में प्लाट्ट के न्यूनतम) पर लगाये गये जहाज की लागत (बिना किसी अपहार या बढ़ागत) को ध्यान में रखते हुए मूल शिखरतम विक्रय मूल्यों का 'आयात साम्य' (Import parity) पर निर्धारण किया जायेगा। उस तारीख से दर्ज किये गये इवराजों (postings) में विभिन्नता नहीं होगी सिवाये जब सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि परिवर्तन न्याय है।

(ख) दल द्वारा संगणित वर्किंग कैपिटल (Working Capital) की आवश्यकताओं को विक्रयों के वार्षिक मूल्य के 1/6 अंश पर पुनः परिकलित किया जायेगा। (1 दिसम्बर 1965 से लागू उत्पादन-शुल्क के केन्द्रीय महसूल के दरों एवं सीमाकर तथा घाट शुल्क को यथोचित ध्यान में रखते हुए)।

5. उपभोक्ताओं के लिए प्रचुर शोधित पेट्रोलियम उत्पादों (और विट्र्यूमेन) के घालू मूल शिखरतम विक्रय मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु शिखरतम विक्रय मूल्यों के ढांचे के विभिन्न तत्वों

(या अंशों) में परिवर्तन हेतु मिनरल प्रोडक्ट्स (उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क के अतिरिक्त दरों) एक्ट, 1958 (1958 का सं० 27) के अन्तर्गत जारी किये गये वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 99/65 के अधीन लगाये गये अतिरिक्त (अप्रत्यादेय) ड्यूटी की दरों में कोई परिवर्तन होंगे।

6. लुब्रीकेण्ट्स/ग्रीज/स्पेशलटीज पर तेल मार्किटिंग कम्पनियों के मार्किटिंग और वितरण प्रभार और लाभ पर 'ब्लॉक कंट्रोल' (Block Control) की वर्तमान पद्धति कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश की गई शिखरतम दरों पर लागू रहेगी। किन्तु उपर्युक्त पैरा 5 में लिखित अधिसूचना दिनांक 26-6-1965 के अनुसार इन उत्पादों पर लगाये गये अतिरिक्त (अप्रत्यादेय) ड्यूटी की दर में परिवर्तन होगा।

7. तेल-उत्पादों के मूल्यों के बारे में उपर्युक्त निर्णय अब से लेकर 31 दिसम्बर 1967 तक लागू रहेंगे और सरकार उनकी बंधता को आगामी अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकती है।

8. कार्यकारी दल के कुछ और सिफारिशों के बारे में सरकार का निर्णय यथा समय घोषित किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघीय प्रदेश प्रशासनों, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिये भारतीय राजपत्र में भी प्रकाशित की जाये।

पी० आर० नायक, सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1966

सं० 35(2)/65-सी० डी० एन० (जी०)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थायी वित्त समिति के विनियमों के विनियम 2(iv) के अधीन, परिषद् की शासी निकाय (गवर्निंग बोर्ड) ने श्री विशम्बर सिंह चौधरी, सदस्य लोक सभा, को 1 अक्टूबर, 1965 से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थायी वित्त समिति का सदस्य निर्वाचित किया है।

जे० पी० वैश्य, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1966

सं० एफ० 2-7/66-रिजार्ग (सी० सी०)—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता (कृषि विभाग—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) के संस्थाप संख्या एफ० 2-7/66-रिजार्ग (सी० सी०), दिनांक 17 फरवरी, 1966 के पैरा 2(3)(II) में लिखे इन शब्दों—“प्रो० एस० धवन, डायरेक्टर, इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्सिज, बंगलौर” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द पढ़े जाएं :

“डा० के० सी० नायक, पी०एच०डी०, उप-कुलपति, यूनिवर्सिटी आफ एग्रिकल्चरल साइंसेज, बंगलौर”।

निर्मल कुमार दत्त, अवर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 1966

सं० एफ० 16-6/65-पी० ई० 4—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 16-6/65-पी० ई० 4, दिनांक 18 दिसम्बर 1965 के क्रम में

डा० ए० एम० डी रोजारियो

संयुक्त सचिव,

शिक्षा मंत्रालय

को श्री बी० पी० बागची के स्थान पर "शारीरिक शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में केन्द्रीय संस्थानों के प्रशासनार्थ सोसायटी" के गवर्नर्स बोर्ड के सदस्य के रूप में आज की तारीख से नामजद किया जाता है।

सं० एफ० 16-1/66-पी० ई० 4—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 16-1/66-पी० ई० 4, दिनांक 17 फरवरी 1966 के क्रम में

श्री बी० आर० गुप्त,

अवर सचिव,

वित्त मंत्रालय

को श्री प्रेम नारायण के स्थान पर लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, म्वालियर के गवर्नर्स बोर्ड के सदस्य के रूप में आज की तारीख से नामजद किया जाता है। वह कालेज के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे।

रोशनलाल आनन्द, अवर सचिव

परिवहन और विमानन मंत्रालय

परिवहन, नौवहन और पर्यटन विभाग

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1966

सं० एस० वाई० 24(4)/65—15 नवम्बर, 1957 में एक समिति जिसका नाम पोत सहायक उद्योग समिति है, स्थापित की गई थी। इसमें पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत से संबंधित विभागों के सरकारी सदस्य थे। इसके विचारार्थ विषय ये थे :—

1. पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत के लिये जरूरी सामग्री और सहायक उपस्कर के प्रमाणित करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करना और सिफारिश करना कि उनमें से किस देश में उत्पादन के लिये प्रमाणित किया जाये जिससे विदेशी मुद्रा व्यय में कमी की जा सके।
2. पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योगों द्वारा आवश्यक सामग्री और सहायक उपस्कर के देसी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों की सिफारिश करना।
3. उपरोक्त सहायक उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रश्न की परीक्षा करना और उपयुक्त सिफारिश करना। इसमें इस बात का विचार रखना होगा कि इस संबंध में परिवहन विभाग किस प्रकार की आवश्यक कार्यवाही कर चुका है।
4. समय-समय पर भेजी जाने वाली तकनीकी समस्याओं की परीक्षा करना और उन पर उचित सिफारिश करना।

2. इस समिति को पुनर्गठित करने का निश्चय किया गया है जिससे विभिन्न विभाग और पोत-निर्माण तथा पोत-मरम्मत उद्योग से संबंधित विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। अतः तीन-वर्षों के लिये 26 फरवरी, 1966 से पोत सहायक उद्योग समिति

पुनर्गठित की गई है। इस अवधि के बाद उसे और आगे रखने की आवश्यकता पर विचार होगा। इसमें निम्न सदस्य होंगे :—

1. श्री एच० पी० नंदा
इस्कर्ट्स लि० कनाट सरकार, नयी दिल्ली अध्यक्ष
2. चीफ आफ मटीरियल, नौसेना, मुख्य-कार्यालय, नयी दिल्ली सदस्य
3. प्रबंधक निदेशक, भारी इंजीनियरी निगम, रांची सदस्य
4. श्री एच० सी० राउत, प्रबंधक निदेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखाभट्टनम् सदस्य
5. श्री एस० मुन्दराराजन, प्रबंधक निदेशक 13/46 गार्डनरीच रोड, कलकत्ता 24 (गार्डन रीच वर्कशॉप लि० कलकत्ता के प्रतिनिधि) सदस्य
6. महानिदेशक, केन्द्रीय यांत्रिक और विद्युत उद्योग, दुर्गापुर सदस्य
7. श्री सी० आर० गोविन्दाराजन, उपमहानिदेशक, नौवहन परिवहन और विमानन मंत्रालय, नयी दिल्ली सदस्य
8. श्री एस० कस्थूरी, निदेशक (यांत्रिक) परिवहन और विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली सदस्य
9. श्री एफ० बी० बदामी, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नयी दिल्ली सदस्य
10. रियर अडमिरल दयाशंकर, भारतीय नौसेना (अवकाश प्राप्त) संख्या—क्यू-4 होजबास, नयी दिल्ली सदस्य
11. भारतीय इंजीनियरिंग संस्था कलकत्ता के मनोनीत सदस्य
12. श्री पी० के० वनर्जी, इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक नौवहन के महानिदेशक का कार्यालय, बंबई सदस्य सचिव
13. श्री बी० आर० राजगोपालन, प्रवर इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक जल परिवहन विभाग, कलकत्ता विकल्प सदस्य सचिव

3. आवश्यकता पड़ने पर समिति को स्थानीय हितों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति का मुख्य कार्यालय बंबई में होगा और पोत सहायक उद्योग समिति से संबंधित सब कार्य नौवहन के महानिदेशालय, कामर्स हाउस, ब्लार्ड स्टेट, बंबई द्वारा किया जायेगा।

5. उपरोक्त समिति पोत मालिकों, पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग के प्रतिनिधियों की जरूरत पड़ने पर सलाह ले सकेगी और अपने काम-काज में उनके प्रतिनिधियों को साक्षी के तौर पर बुला सकेगी। समिति को सरकार की आज्ञा से किसी विशेष समस्या पर एक या दो विदेशी विशेषज्ञों को बुला कर परीक्षा करने का अधिकार होगा। इसके अलावा समिति पोत मालिकों और अन्य संबंधित हितों के व्यावहारिक और जानेवाले व्यक्तियों को सहयोजित भी कर सकेगी।

6. समिति तीन महीने में एक बार किन्तु वर्ष में चार बार से अधिक बैठक नहीं करेगी और उनके द्वारा किये गये काम, सिफारिशों और सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देगी।

7. समय-समय पर जारी हुये केन्द्रीय सरकार के अधीन दिये जाने वाले सहंगाई भत्ता/यात्रा भत्ता के अधिकारी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य होंगे। फिर भी, सरकारी सदस्य अपना यात्रा/सहंगाई भत्ता अपने संबंधित विभागों/कार्यालयों से लेंगे।

गोपाल लाल मलहोत्रा, अवर सचिव
रुते सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1966

सं० 65/डबल्यू० 4/सी०एन०एल०/डबल्यू०/15—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने राजकोट-जासदन (61.16 किलो मीटर, मीटर-लाइन) और भावनगर-तारापुर (140.82 किलो मीटर, बड़ी लाइन) की प्रस्तावित नयी लाइनों के लिए नये यातायात सर्वेक्षण करने की मंजूरी दे दी है। इन सर्वेक्षणों को पश्चिम रेल-प्रशासन राजकोट-जासदन और भावनगर-तारापुर सर्वेक्षण के नाम से करेगा।

पी० सी० मैथ्यू, सचिव, रेलवे बोर्ड

सिन्हाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 1966

सं० वि० का० 5-515(7)/63—तट कटाव समस्या पर और इसको वैज्ञानिक और समन्वित आधार पर सुलझाने के लिये आवश्यक उपायों पर कुछ समय से भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। यह समस्या केरल में विकट है और वहां पर तट रेखा का एक लम्बा भाग पहले से ही प्रभावित है। इस बारे में केरल के परिकल्पित कार्यक्रम का सूत्रपादन करने, निर्देशन करने और कार्यान्वयन करने के लिये भारत सरकार ने केरल सरकार से सलाह करके एक तट कटाव बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है।

2. तट-कटाव बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग,
नई दिल्ली अध्यक्ष
2. विकास सलाहकार (पत्तन), परिवहन तथा
विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली सदस्य
3. डा० एम० मनोहर, प्रोफेसर तथा सिविल
इंजीनियरी विभाग के मुख्य अधिकारी,
मौलाना आजाद टेक्नोलॉजी कालेज,
भोपाल सदस्य
4. निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा
केन्द्र, पुना सदस्य
5. मुख्य अभियन्ता (समुद्र-कटाव-रोध कार्य,
केरल सरकार द्वारा मनोनीत होने वाला) सदस्य-सचिव

3. बोर्ड अपनी बैठकें ऐसे स्थानों पर करेगा जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और अपनी बैठकों में ऐसे अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों को बुलाएगा जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझेगा। जितनी बार बोर्ड आवश्यकता समझेगा, अपनी बैठकें बुलाएगा परन्तु एक वर्ष कम-से-कम दो बार बैठकें अवश्य ही बुलाई जाएंगी।

4. बोर्ड किसी भी विशेष उद्देश्य के लिये ऐसी समितियां या उप-समितियां नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे।

5. बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (1) विविध प्राकृतिक घटनाओं और तटीय गतिविधियों के सम्बन्ध में, जो कि तट रेखा को प्रभावित करती हैं, आंकड़ों के एकत्रण, संकलन, मूल्यांकन और प्रकाशन का प्रबन्ध और समन्वय करना।
- (2) तट इंजीनियरी कार्यों के अभिकल्पों के सम्बन्ध में गवेषणा तथा उनके विकास को उद्यत तथा समन्वित करना।
- (3) राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारों द्वारा बनाए गए 5.5 लाख रुपये की लागत के तट सुरक्षा कार्यों का पुनरवलोकन करना तथा उनके लिये तकनीकी स्वीकृति देना।
- (4) तट-कटाव अध्ययन में रक्षा कार्यों को हाथ में लेने के लिये तकनीकी सहायता का प्रबन्ध करना।
- (5) तट इंजीनियरी में लगे हुए व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध करना।
- (6) मितव्ययी और समन्वित तरीके से तट-कटाव समस्या को सुलझाने के लिये ऐसे दूसरे पग उठाना जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों और संघीय प्रदेशों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और परिवहन तथा विमानन, सुरक्षा, शिक्षा, वित्त (व्यय विभाग) व (समन्वय विभाग), गृह, रेलवे, निर्माण तथा आवास व नगर विकास मंत्रालयों को सूचनार्थ भेज दिया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाये कि वे भी इस संकल्प को राज्यों के राजपत्रों में आम जानकारी के लिये प्रकाशित कर दें।

के० पी० मथरानी, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1966

सं० वि० का० अनु० 5-502(10)/65—इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का० अनु० 5-502(10) 65, दिनांक 5 जून, 1965 के सांतत्य में वरक बांध परियोजना के सम्बन्ध में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति का पुनरवलोकन करने के लिये तथा आया बांध का निर्माण करना है अथवा वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया जाना है इस पर विचार करने के लिये स्थापित तकनीकी समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट की प्रस्तुत करने की तिथि को 31 मार्च, 1966 तक और बढ़ा दिया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को असम सरकार, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक और योजना आयोग को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और असम सरकार से प्रार्थना की जाए कि वे भी इसे साधारण सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दें।

पी० आर० अहूजा, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT*New Delhi, the 17th March 1966***CORRIGENDUM**

No. 31-Pres/66.—In this Secretariat Notification No. 41-Pres/65, dated the 23rd June 1965, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday the 3rd July 1965, instituting the "LADAKH-1962" and "NEFA-1962" Clasps, the following amendment should be made in Para 2 II(a) (v) :—

For the date "26th October" read "25th October".

V. J. MOORE, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION*New Delhi, the 24th February 1966***RESOLUTION**

(Advisory Committee on Irrigation, Flood Control and Power Projects).

No. III-1(2)/65-I & P.—The following amendment is made in the Government of India, Planning Commission Resolution No. III-1(2)/65-I & P dated 2-7-1965 as modified vide Planning Commission addendum dated 27-12-1965. In Para (4) of the Resolution dated 2-7-1965 relating to the composition of the Advisory Committee on Irrigation, Flood Control and Power projects, *against item (i)*.

Read "Minister of State for Irrigation and Power—Chairman."

For "Deputy Minister for Irrigation and Power—Chairman."

Against item (vi)

Read "President or a past President, Institution of Engineers (India)."

For "President, Institution of Engineers (India)."

Against item (xii)

Add "A representative of Atomic Energy Commission."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Chief Ministers of States, all Ministries of the Government of India, the Prime Ministers Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President.

ORDERED also that a copy be published in the Gazette of India for general information.

G. R. KAMAT, Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS*New Delhi, the 14th March, 1966*

No. 17-5-65-Poll. I.—The following statement showing the number of persons in detention under the Preventive Detention Act, 1950 (4 of 1950) in various States as on the 30th June, 1965, is published for general information.

Number of persons in detention under the Preventive Detention Act, 1950 on the 30th June, 1965						
Name of the State	Detained under section 3(1)(a)			Total of Columns 2—4	De-tained under Section 3(1)(b)	Grand Total
	Clause					
	(i)	(ii)	(iii)			
	(1)	(2)	(3)			
1. Andhra Pradesh ..	—	—	—	—	—	—
2. Assam ..	—	—	—	—	—	—
3. Bihar ..	—	—	—	—	—	—
4. Gujarat ..	—	6	—	6	—	6
5. Kerala ..	—	—	—	—	—	—
6. Madhya Pradesh ..	—	—	—	—	—	—
7. Madras ..	—	—	—	—	—	—
8. Maharashtra ..	—	12	—	12	—	12
9. Mysore ..	—	—	—	—	—	—
10. Orissa ..	—	1	—	1	—	1
11. Punjab ..	—	—	—	—	—	—
12. Rajasthan ..	—	—	—	—	—	—
13. Uttar Pradesh ..	—	9	—	9	—	9

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. West Bengal ..	—	—	34	—	34	—	34
15. Delhi ..	—	—	—	—	—	—	—
16. Himachal Pradesh ..	—	—	—	—	—	—	—
17. Manipur ..	—	—	—	—	—	—	—
18. Tripura ..	—	—	—	—	—	—	—
19. Nagaland ..	—	—	—	—	—	—	—
20. N.E.F.A. ..	—	—	—	—	—	—	—
	—	62	—	62	—	62	

B. S. RAGHAVAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Expenditure)***New Delhi, the 17th March 1966*

No. 1060-PTI/66.—The President hereby directs that the following further amendments shall be made in the Rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

In the said Rules, in the second sentence of Rule 28, for the words "rupees five thousand," the words "rupees three thousand" shall be substituted.

C. B. GULATI, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE*New Delhi, the 10th March 1966*

No. 1(6)-Tex(I)/65.—In the Government of India, Ministry of Commerce Resolution No. 3(9)-Tex(A)/64, dated the 27th October 1964 published in the Gazette of India Extraordinary Part 1 Section 1 dated the 27th October, 1964, the following amendment shall be made, namely :—

In the said Resolution, for serial number 1 of paragraph 2 the following shall be substituted, namely,

"1. Shri Mohd. Shafi Qureshi, Deputy Minister of Commerce, Government of India, New Delhi."

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION**(Department of Agriculture)****I.C.A.R.***New Delhi, the 18th March 1966*

No. 35(2)/65-CDN(G).—Under Regulation 2(iv) of the Regulations of the Standing Finance Committee of the Indian Council of Agricultural Research, Shri Digambar Singh Chaudhuri, Member, Lok Sabha, has been elected by the Governing Body of the Council as its representative on that Committee for a period of one year with effect from the 1st October 1965.

J. P. VAISH, Under Secy.

*New Delhi, the 19th March 1966***CORRIGENDUM**

No. F. 2-7/66-Reorgn(CC).—In para 2(3)(ii) of Resolution No. F. 2-7/66-Reorgn(CC), dated the 17th February 1966 of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Deptt. of Agriculture-ICAR) the words "Prof. S. Dhawan, Director, Indian Institute of Sciences, Bangalore" shall be substituted by the following words :—

"Dr. K. C. Naik, Ph.D., Vice-Chancellor, University of Agricultural Sciences, Bangalore".

N. K. DUTTA, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION*New Delhi, the 16th March 1966*

No. F. 2-6/63-PE2.—In continuation of the Ministry of Education Notification of even number dated the 19th February 1966,

Air Commodore C. L. Mehta, President, Services Sports Control Board,

is nominated on the Board of Governors of the National Institute of Sports, Patiala as *Ex-officio* member, till 24-7-1966 vice Major General Jagjit Singh Aurora.

R. L. ANAND, Under Secy.

New Delhi, the 18th March 1966

No. F. 16-1/66-PE.4.—In continuation of the Ministry of Education Notification No. F. 16-1/66-PE.4, dated the 1st March 1966 :

SHRI R. L. ANAND
UNDER SECRETARY
MINISTRY OF EDUCATION.

is nominated as Member of the Board of Governors of "Lakshminbai College of Physical Education, Gwalior", with immediate effect *vice* Shri K. C. S. Acharya.

A. M. D'ROZARIO, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 16th March 1966

RESOLUTION

No. 24/12/65-SCT.III(B).—In partial modification of the Department of Social Security Resolution No. 22/5/64-SCT.III(B), dated 23-4-65 [as extended by Resolution No. 24/12/65-SCT.III(B), dated 16-11-65], it has been decided that Shri H. K. Chaudhry, Deputy Legal Adviser, Ministry of Law will act as Legal Adviser to the Committee on Customary Rights to Scavenging instead of as a Member.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. C. SEN GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport, Shipping and Tourism)

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th February 1966

No. SY-24(4)/65.—A Committee known as Ship Ancillary Industries Committee, was set up with effect from 15th November 1957, with a composition of only official members of Departments concerned with the Ship-building and Ship-repairing industry, with the following terms of reference :—

- (i) to discuss the question of standardising the material and ancillary equipment required for ship-building and ship-repair work and recommend which of them should be standardised for production in the country so as to minimise the foreign exchange expenditure;
- (ii) to recommend on the steps to be taken to encourage the indigenous production of material and ancillary equipment required by the Ship-building and Ship-repairing industries;
- (iii) to examine the question of the training of personnel required for the development of the above ancillary industries and make suitable recommendations, keeping in view the steps that are already being taken by the Department of Transport in this connection; and
- (iv) to examine other technical problems which may be referred to it from time to time and make suitable recommendations thereon.

2. It has now been decided to reconstitute this Committee in order that various Departments, interests connected with the Ship-building and Ship-repairing industry be represented. Accordingly the Ship Ancillary Industries Committee, has been reconstituted with effect from 26th February 1966, for a period of three years after which the need for its further continuance will be reviewed, and with the following composition of the members :—

Chairman

1. Shri H. P. Nanda,
Escorts Ltd., Connaught Circus,
New Delhi.

Members

2. Chief of Material, Naval Headquarters,
New Delhi.
3. The Managing Director, Heavy Engineering
Corporation, Ranchi.
4. Shri H. C. Raut,
Managing Director,
Hindustan Shipyard Ltd.,
Visakhapatnam.

5. Shri S. Soundra Rajan,
Managing Director,
43/46, Garden Reach Road,
Calcutta-24. (Representative of
Garden Reach Workshop Ltd. Calcutta)
6. Director General,
Central Mechanical & Electrical
Industries,
Durgapur.
7. Shri C. R. Govindarajan,
Deputy Director General of Shipping,
Ministry of Transport & Aviation,
New Delhi.
8. Shri S. Kasthuri,
Director (Mechanical),
Ministry of Transport & Aviation,
New Delhi.
9. Shri F. V. Badami,
Development Officer,
Directorate General of Technical
Development,
New Delhi.
10. Rear Admiral Deya Shankar, I.N. (Retired)
No. Q-4, Hauz Khas,
New Delhi.
11. A nominee of Indian Engineering
Association, Calcutta.

Member-Secretary

12. Shri P. K. Banerjee,
Engineer & Ship Surveyor,
Office of Director General of Shipping,
Bombay.

Alternate Member-Secretary

Shri V. R. Rajagopalan,
Senior Engineer and Ship Surveyor,
Mercantile Marine Department,
Calcutta.

3. The Committee shall have power to co-opt. representatives of local interests as members for a meeting, if necessary.

4. The Committee will have its Headquarters at Bombay and all work connected with the Ship Ancillary Industries Committee will be carried out by the Directorate General of Shipping, Commerce House, Ballard Estate, Bombay.

5. The above Committee may consult the Shipowners, representatives of the Ship-building and Ship-repairing industries and if necessary, examine their representatives as witnesses during the course of their deliberations. The Committee is also authorised to invite and examine, with the permission of the Government, one or two foreign experts on particular problem. Further the Committee may co-opt. a knowledgeable and practical person from among the ship owners and of other connected interests.

6. The Committee will meet once in three months and not more than four times in a year and will report annually to Government the work done by them, their recommendations and the implementation of the latter.

7. The official and non-official members will be entitled to DA/TA as admissible under the Central Government rules issued from time to time. However, the official members will draw their TA/DA from their respective Departments/offices, etc.

NAGENDRA SINGH, Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 15th February 1966

No. 65/W4/CNL/W/15.—It is hereby notified for general information that the Ministry of Railways (Railway Board) have sanctioned new traffic surveys for Rajkot-Jasdan (61.16 KMs. metre gauge) and Bhavnagar-Tarapore (140.82 KMs. broad gauge) proposed new railway lines. The surveys will be carried out by the Western Railway Administration and will be known as Rajkot-Jasdan and Bhavnagar-Tarapore Traffic Surveys.

P. C. MATHEW, Secy., Rly. Board.